

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादून: दिनांक 03 जनवरी
दिसम्बर, 2005

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-152/तेरह-31(2004-05) दिनांक 20.10.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु 2 कार्यो के रु० 12.39 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार संलग्न विवरणानुसार रु० 11,80,000/- (रु० ग्यारह लाख अस्सी हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की स्वीकृति भी श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3- कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार हैं अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4- कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मैजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका संत्यापन अधि०अभि० स्वयं करें।

5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हैं एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित हैं। सूची में जो कार्य नये हों उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7- कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको सनायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी

द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस रूप में पुष्टि हो जाये।

8- दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यों का यथास्थान चिन्हां एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का

9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10- उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जाय अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्ड

11- कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य

उ-राक्षण
किया जायेगा।
जनताओं की फोटो लेकर
स्थता का प्रमाणीकरण किया जा

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

13- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्यय अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 आपदा राहत निधि-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें- 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या- 110/वित्त अनु0 5/2005 दिनांक 27.12.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) औबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
- 3- अपर सचिव, नियोजन विभाग।
- 4- कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 7- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
- 8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 9- वित्त अनुभाग-5,
- 10- धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

देहरादून: दिनांक

03 जनवरी 2006
दिसम्बर, 2005

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

विषय:-

उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा स्थापित लघु जल विद्युत परियोजना कनौलगाड़ जनपद बागेश्वर के दिनांक 02 एवं 03 सितम्बर, 2005 में आयी भारी वर्षा एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिविल कार्यों के क्षतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा जनपद बागेश्वर क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त लघु जल विद्युत परियोजना के मरम्मत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये रु0 7.12 लाख के आगणन के विपरीत तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रु0 6,20,000/- (रु0 छः लाख बीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

- 1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।
- 2- कार्य कराने से पूर्व सनस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 3- कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- 4- कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत / मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में रिलप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।
- 5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित / स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि कार्यवाही संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।
- 7- कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा

जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।

8- दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यों का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10- उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11- कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

13- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्यय अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 आपदा राहत निधि-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें- 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या- 109/वित्त अनु0 5/2005 दिनांक 27.12.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- निदेशक, उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, देहरादून।
- 2- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
- 3- अपर सचिव, नियोजन विभाग।
- 4- कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 5- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 7- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
- 8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 9- वित्त अनुभाग-5.
- 10- धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

बी. के. पाटक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवानें,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

विषय:-

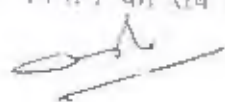
जनपद ऊधमसिंहनगर क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

देहरादून: दिनांक 03 जनवरी
दिसम्बर, 2006

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 131/तेरह-सी.आर.ए./2005 दिनांक 5.8.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंहनगर क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत के 9 कार्यों के रु० 88.99 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार संलग्न विवरणानुसार रु० 73.76,000/- (रु० तीहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

- 1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।
- 2- कार्य कराने से पूर्व सनस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 3- कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार हैं अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- 4- कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत / मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मैजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि०अभि० स्वयं करें।
- 5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित / स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था नगर पालिका परिषद बाजपुर को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हों, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय। स्वीकृत धनराशि से मार्ग मरम्मत का कार्य ही किया जायेगा, नाली निर्माण कार्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 7- कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको सनायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था / विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।



41C-1596

- 8- देवी आपदा राहत निधि से कृत कार्य का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।
- 9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए जिलाधिकारी एवं संबंधित निर्माण एजेन्सी नगर पालिका परिषद्, जसपुर तथा अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी की देख रेख में कार्य सम्पादित किया जायेगा।
- 10- उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमत्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
- 11- कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेंगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।
- 12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
- 13- देवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत उक्त धनराशि अदस्थापना निधि में रखी जायेगी जो आवश्यकतानुसार ही जिलाधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय की जायेगी।
- 14- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्यय अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 आपदा राहत निधि-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-01-केंद्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें- 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
- 15- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या- 235/वित्त अनु0 5/2005 दिनांक 27.12.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) आंबेराय बिल्डिंग, नाजरा, देहरादून।
- 2- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
- 3- अपर सचिव, नियोजन विभाग।
- 4- कोषाधिकारी, ऊधनसिंहनगर।
- 5- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 7- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
- 8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 9- वित्त अनुभाग-5,
- 10- धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादून: दिनांक 03 नवम्बर, 2006

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-209/तेरह-24(2004-05) दिनांक 25.10.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु 2 कार्यो के रु0 12.09 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार संलग्न विवरणानुसार रु0 11,30,000/- (रु0 ग्यारह लाख तीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की स्वीकृति भी श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2- कार्य कशने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते सनय पालन करना सुनिश्चित करें।

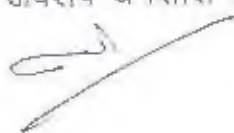
3- कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4- कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत / मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मैजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित / स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हों उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7- कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी



11-13
धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।

- 8- दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यों का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।
- 9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 10- उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होंगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
- 11- कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।
- 12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
- 13- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्यय अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 आपदा राहत निधि-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें- 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या- 114/वित्त अनु0 5/2005 दिनांक 30.12.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
- 3- अपर सचिव, नियोजन विभाग।
- 4- कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 7- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
- 8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 9- वित्त अनुभाग-5,
- 10- धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

देहरादून: दिनांक 03 जनवरी, 2006

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यों की वर्ष 2005-06 में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प.सं. 1927/तेरह-66/2005-06, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रांतर्गत जौलजीबी-मुनस्यारी मोटर मार्ग के कि.मी. 44 में मन्दाकिनी नदी पर 36.6 मीटर स्पान के वैली ब्रिज निर्माण कार्य हेतु रु0 99.08 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रु0 94,20,000/- (रु0 चौरानवें लाख, बीस हजार मात्र) की लागत के आगणन (प्रति संलग्न) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।
- 2- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 3- कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार हैं अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- 4- कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में रिलप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।
- 5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। फील्ड मरम्मत का कार्य नहीं किया जायेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित हैं। सूची में जो कार्य नये हों, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।
- 7- कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको

14/1398

समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।

8- दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्य का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेंसी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेंसी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10- उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11- कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्यय अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 आपदा राहत निधि-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें-0101 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय(75 केन्द्रांश)-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या- 107/वित्त अनु0 5/2005 दिनांक 27.12.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वी. के. पाठक)

अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
- 4- अपर सचिव, नियोजन विभाग।
- 5- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
- 6- कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 9- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
- 10- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- वित्त अनुभाग-5,
- 12- धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(वी. के. पाठक)

अपर सचिव

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

आपदा प्रदग्धन एवं पुनर्वास

देहरादून: दिनांक 03 जनवरी, 2006

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु धनराशि की वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3520/13-27(2004-2005) (मु.रा.ले.) दिनांक 26.9.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत के 7 कार्यो के रु0 44.727 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रु0 33,61,000/- (रु0 तैतीस लाख इकसठ हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3- कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4- कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7- कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी

द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।

8- दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यों का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेंसी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित निर्माण एजेंसी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10- उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11- कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

13- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्यय अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 आपदा राहत निधि-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें- 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या- 221/वित्त अनु0 5/2005 दिनांक 31.12.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
- 3- अपर सचिव, नियोजन विभाग।
- 4- कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 5- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 7- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
- 8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 9- वित्त अनुभाग-5।
- 10- धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादून: दिनांक २६ जनवरी, 2006

विषय:- जनपद नैनीताल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 07/13-सी.आर.एस./2004 दिनांक 7.5.2005 एवं प.सं. 1844-1/13-सी.आर.एस./2005 दिनांक 4.7.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त रिंग रोड दुल्हेपुरी परमजीत सिंह आदि के घर तक होते हुये काशीपुर रोड तक सी.सी. मार्ग पुर्ननिर्माण कार्य हेतु रु० 9.51 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रु० 8,49,000/- (रु० आठ लाख उन्चास हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3- कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4- कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि०अभि० स्वयं करें।

5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हों, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7- कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा



जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।

8- दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यों का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेंसी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेंसी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10- उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11- कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

13- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्यय अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 आपदा राहत निधि-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें- 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या- 10/वित्त अनु0-5/2006 दिनांक 02 जनवरी, 2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(वी. के. पाठक)

अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 3- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
- 4- अपर सचिव, नियोजन विभाग।
- 5- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तरांचल।
- 6- कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 7- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 9- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 10- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
- 11- वित्त अनुभाग-3, ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)

अपर सचिव